नईदुनिया

संपादकीय

बच्चों के लिए मौत के बोरवेल

ऐसे समय में जब देश-दुनिया नये साल के जश्न में डूबने जा रही है मध्यप्रदेश व राजस्थान में खुले बोरवेल में गिरने से हुई दो बच्चों की मौत विचलित करती है। राजस्थान के दोसा जिले और मध्यप्रदेश के गुना की घटनाएं पहली बार नहीं हुई हैं। गाहे-बगाहे ऐसी खबरें पूरे देश से आती हैं। यह सोचकर ही मन सिहर उठता है कि कोई बच्चा कैसे एक अंधी सुरंग में भूखे-प्यासे, अपर्याप्त ऑक्सीजन व बिना हिले-डुले कुछ दिन मौत की प्रतीक्षा करता होगा। भय व घुप्प अंधेरे में बच्चा किन मानसिक व शारीरिक यातनाओं से गुजरता होगा, सोचकर भी डर लगता है। लेकिन फिर भी हमारा संवेदनहीन समाज व लापरवाह तंत्र इस त्रासदी को गंभीरता से नहीं लेता। जिस बोरवेल को खुदवाने में लाखों रुपये खर्च होते हैं, उसका मुंह बंद करने के लिये चंद रुपये खर्च करने में लोग आपराधिक लापरवाही दिखाते हैं। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी तीन साल की बच्ची को एक सप्ताह बाद भी न निकाला जाना तंत्र की विफलता को दर्शाता है। नि:संदेह, यह अभियान जटिल बताया जाता है और बारिश ने राहत कार्य में बाधा डाली, लेकिन शुरुआत में प्रशासन की शिथिलता पर सवाल उठे हैं। ऐसे अभियानों में राष्ट्रीय आपदा निरोधक बल तथा स्थानीय सुरक्षा बलों की नाकामी गाहे-बगाहे उजागर होती रहती है। नि:संदेह, ऐसे संकटों में तत्काल कार्रवाई और राहत- बचाव कार्य को आधुनिक तकनीक से शुरू करने की जरूरत महसूस की जाती रही है। यही वजह है कि आए दिन होने वाले बोरवेल हादसों के मद्देनजर देश की शीर्ष अदालत ने वर्ष 2010 में इस बाबत दिशानिर्देश जारी किए थे ताकि ऐसे हादसों को टाला जा सके। जिसमें बोरवेल के चारों ओर बाड़ लगाने तथा मजबूत बोल्ट के साथ स्टील कवर लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद आए दिन बोरवेल में बच्चों के गिरने के मामले सामने आ रहे हैं। जाहिर किसान व स्थानीय प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी कर रहे हैं। अन्यथा ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न होती।

नि:संदेह, देश के विभिन्न भागों में बोरवेल हादसों का सामने आना जहां निगरानी करने वाले विभागों की लापरवाही को दर्शाता है, वहीं उन लोगों के आपराधिक कृत्य को भी दर्शाता है, जो बोरवेल का मुंह खुला छोड़ देते हैं। वहीं हादसे हमारे समाज में चेतना के अभाव को भी दर्शाते हैं कि खुले बोरवेल के खिलाफ आम लोगों के स्तर पर आवाज नहीं उठायी जाती। यह भी उल्लेखनीय है कि सिंचाई विभाग राज्यों का विषय होने के कारण इसमें केंद्र सरकार का दखल नहीं हो पाता। एक अनुमान के अनुसार देश में करीब पौने तीन करोड़ बोरवेल हैं। जिसमें से बड़ी संख्या में सूख चुके हैं। जिन्हें गैरजिम्मेदार लोगों द्वारा खुला छोड़ दिया जाता है, जो कालांतर हादसे की वजह बन जाते हैं। विडंबना यह भी है कि एनडीआरएफ द्वारा चलाये जाने वाले ऐसे राहत व बचाव के दो तिहाई अभियान नाकाम रहते हैं। दरअसल, सभी राज्यों में ऐसे मामलों में बच्चों की जान बचाने से जुड़े सुरक्षा उपाय हर जिले के अधिकारियों को एक मैनुअल के रूप में दिए जाने चाहिए। ताकि किसी हादसे के बाद राहत-बचाव कार्य तुरंत शुरू करके बच्चों को बचाया जा सके। संकट इस ओर भी इशारा करता है कि ऐसे मामलों में हमारा राहत व बचाव का तंत्र कितना शिथिल व निष्प्रभावी है। अकसर स्थिति जटिल होने पर सेना के विशेषज्ञों की भी मदद ली जाती है।

कई बार इतनी देर बाद सेना के विशेषज्ञों को बुलाया जाता है कि बच्चों के बचने की उम्मीद क्षीण हो चुकी होती है। निश्चित रूप से बोरवेल की देखरेख करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का वक्त आ गया है। ऐसे मामलों में लापरवाही दिखाने वाले अधिकारियों को दंडित करने की जरूरत है। उनका दायित्व बनता है कि खुले बोरवेल के मालिकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। समाज के लोगों को भी इस बाबत सचेत करने की जरूरत है ताकि वे प्रशासन को खुले बोरवेल की सूचना दे सकें। यदि समाज सचेत और संवेदनशील रहेगा तो उसका दबाव प्रशासन भी महसूस करेगा। फिर इस सजगता-सतर्कता से कई बच्चों की अनमोल जिंदगी बचायी जा सकेंगी।

मोदी युग: मानसिक स्वास्थ्य का क्रांतिकाल

शिवेश प्रताप

3 दिसंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने मानसिक स्वास्थ्य के लिए मोदी सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया। एक ऐसा विषय जिसने मोदी सरकार के इस उत्कृष्ट प्रयास के बारे में बहुत जरूरी चर्चा को जन्म दिया है। मोदी युग ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को संबोधित करने और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को मुख्यधारा की स्वास्थ्य देखभाल नीतियों में एकीकृत करने पर अधिक ध्यान दिया गया। मोदी सरकार से पहले, भारत में मानसिक स्वास्थ्य को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया और मानसिक बीमारियों को लेकर लोगों में शर्म और भ्रान्ति थी। नरेन्द्र मोदी के शासन में मानसिक स्वास्थ्य को महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में मान्यता देने की दिशा में बदलाव हुआ।

मानसिक स्वास्थ्य और इसका महत्व-भारत में मानसिक स्वास्थ्य गलत समझा जाने वाला विषय बना हुआ था। लगभग 14 प्रतिशत भारतीयों को सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता होने के बावजूद, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) में पाया गया कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं वाले लगभग 80 प्रतिशत लोग सामाजिक कलंक, जागरूकता की कमी या देखभाल तक सीमित पहुँच के कारण मदद नहीं लेते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ मानसिक बीमारी का न होना नहीं है; इसमें भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कल्याण शामिल है, जो व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। एक स्वस्थ दिमाग उत्पादक जीवन, सामंजस्यपूर्ण समाज और संपन्न अर्थव्यवस्था का आधार है। भारत जैसे देश के लिए जो 2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने की आकांक्षा रखता है, मानसिक स्वास्थ्य को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे में एकीकृत करना अनिवार्य है।

भारत का मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य: भारत एक गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, भारत की लगभग 7.5त्न आबादी मानसिक विकारों से पीड़ित है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) से पता चला है कि लगभग 15 प्रतिशत भारतीय वयस्कों को सक्रिय मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप की आवश्यकता है, मानसिक स्वास्थ्य ख़राब है और इसके लिए पर्याप्त धन नहीं है। चौंकाने वाली बात यह है कि देश में प्रति 100,000 लोगों पर एक से भी कम मनोचिकित्सक हैं, जबकि डब्ल्यूएचओ ने प्रति 100,000 पर तीन मनोचिकित्सक होने की सिफारिश की है। भारत में मानसिक विकारों के लिए उपचार का अंतर 70-92 प्रतिशत के बीच है और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान का अनुमान 2012 और 2030 के बीच 1.03 ट्रिलियन डॉलर है। ऐसे चौंकाने वाले आँकड़े मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए मजबूत नीतियों और बुनियादी ढाँचे की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। अमेरिका मानसिक स्वास्थ्य पर सालाना 238 बिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च करता है, जहाँ हर 100,000 लोगों पर लगभग 12 मनोचिकित्सक हैं। इसी तरह, यूरोप में मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली अच्छी तरह से विकसित है, जहाँ जर्मनी जैसे देश हर 10,000 लोगों पर 18 से ज़्यादा मनोरोग विशेषज्ञ उपलब्ध कराते हैं। इस बीच, चीन में 2013 में अपने पहले मानसिक स्वास्थ्य कानून के बाद से मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ी है।

मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017: एक महत्वपूर्ण मोड़-मोदी के नेतृत्व में सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को संबोधित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के दौरान पेश किया गया था, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इसके निर्माण और परिचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह अधिनियम भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था और मई 2018 में लागू हुआ।

अधिनियम का सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि यह मानसिक बीमारी को मानवाधिकार के मुद्दे के रूप में मान्यता देता है, यह सुनिश्चित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति वाले व्यक्तियों के साथ बहिष्कृत जैसा व्यवहार न किया जाए, बल्कि वे कानून के तहत देखभाल, उपचार और सुरक्षा के हकदार हों। अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली में एकीकृत करके और यह सुनिश्चित करके कि सेवाएँ सभी स्तरों पर उपलब्ध हों। यह आत्महत्या के अपराधीकरण पर भी जोर देता है और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति दयालु, पुनर्वास दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है।

आयुष्मान भारत के तहत व्यापक मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल करना, जिन्हें अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकार ने 1.73 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सफलतापूर्वक अपग्रेड किया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ जमीनी स्तर पर उपलब्ध हों। ये केंद्र अब मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करते हैं, जिसमें आउटपेशेंट परामर्श, मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, मूल्यांकन, परामर्श, निरंतर देखभाल और आवश्यक दवाओं तक पहुँच शामिल है। यह दृष्टिकोण मानसिक बीमारियों का शीघ्र पता लगाना और उनका प्रबंधन सुनिश्चित करता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कलंक और बाधाओं को कम किया जा सकता है।

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम: स्थानीय स्तर पर कमियों को दूर करना-767 जिलों में लागू जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) तक सेवाओं का विस्तार करके भारत के मानसिक स्वास्थ्य ढांचे को काफी मजबूत किया गया है। यह देखभाल का एक मजबूत नेटवर्क प्रदान करता है, जिसमें आउट पेशेंट देखभाल, मनो-सामाजिक परामर्श, आउटरीच कार्यक्रम और एम्बुलेंस सेवाओं जैसी आवश्यक सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। यह व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप वंचित और कमज़ोर आबादी तक पहुँचे, जिससे कल्याण के समग्र मॉडल को बढ़ावा मिले।

राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम: डिजिटल क्रांति-10 अक्टूबर, 2022 को लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनटीएसएचपी) मानसिक स्वास्थ्य सेवा में एक डिजिटल छलांग का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में एनटीएसएचपी के लिए क्रमश: 120.98 करोड़, 133.73 करोड़ और 90 करोड़ आवंटित किए हैं। देशभर में संचालित एक टोल-फ्री हेल्पलाइन (14416) के साथ, यह कार्यक्रम 20 भाषाओं में 24×7 टेली-परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है, जिससे सभी के लिए पहुँच सुनिश्चित होती है। नवंबर 2024 तक, 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 53 टेली-मानस सेल स्थापित किए गए हैं, जो 15.95 लाख से अधिक कॉल संभालते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2024 पर लॉन्च किया गया टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

सरसंघचालक के बयान पर विवाद: हिंदुओं को व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा

नजरिया

-पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

हमारे देश और दुनिया भर में संघर्षों ने हर देश, धर्म और समुदाय में दुख और तनाव पैदा किया है। दुनिया ने विश्वव्यापी शांति के लिए एक अच्छा जवाब खोजने में अपना रास्ता खो दिया है। सनातन धर्म ने पहले ही सार्वभौमिक भाईचारे और शांति का मार्ग प्रदर्शित किया है और हाल के दिनों में, दुनिया एक बार फिर शांति और सद्भाव बहाल करने में सनातन धर्म की शक्ति को देख और मान रही है। दुनिया भर में कई लोगों ने सनातन धर्म का पालन करना शुरू कर दिया है। कई और सही समय का इंतजार कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहनजी भागवत द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित नवीनतम मुद्दे ने मुख्यधारा के मीडिया, सोशल मीडिया और हिंदुओं के बीच रोष पैदा कर दिया है, हर मंच पर उन पर और आरएसएस पर घृणा की बौछार की जा रही है। कुछ टिप्पणियाँ तो बिल्कुल अस्वीकार्य हैं। मीडिया आउटलेट अक्सर टीआरपी बढ़ाने और सनातन धर्म समर्थकों के बीच विवाद भड़काने के लिए पीएम मोदी और सरसंघचालक मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयानों पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। चूंकि हिंदू औपनिवेशिक मानसिकता के रूप में जानी जाने वाली मानसिकता के शिकार रहे हैं, जिसने उन्हें सोचने में कमजोर बना दिया है इसलिए कई हिंदुओं ने विश्लेषणात्मक एवं शोध करने का नजरिया खो दिया है। कई हिंदुओं ने मुख्यधारा के मीडिया द्वारा दिखाए गए एक या दो लाइनों पर प्रतिक्रिया देने की आदत बना ली है, बिना तथ्यों की गहराई से जांच किए, विश्लेषण किए और अध्ययन किए कि यह क्यों कहा गया।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि यह कई बार साबित हो चुका है कि जब भी वर्तमान या पिछले आरएसएस सरसंघचालकों ने कोई सार्वजनिक बयान दिया तो उसका गहरा अर्थ था, जिसे समय के साथ सभी ने समझा इसलिए हिंदुओं को पिछले अनुभवों से सीखना चाहिए। सबसे पहले यह समझना चाहिए कि क्या कहा गया है और इन बयानों के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ हिंदू उन्हें और संघ को हिंदुत्व के बारे में सिखा रहे हैं, जबकि कुछ उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं जानने और हिंदू मान्यताओं को ठेस पहुंचाने के लिए निंदा कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति या संगठन के लिए इस तरह के वाक्यांश का उपयोग करना शर्मनाक है, जिसके कई स्वयंसेवकों ने हिंदुओं, हिंदुत्व और भारत माता के लिए अपने आनंद भरे व्यक्तिगत जीवन और अपनी मानसिक इच्छाओं को त्याग दिया है। फिर भी उनकी ईमानदारी को चुनौती देना सूर्य से यह पूछने जैसा है कि क्या वह ऊर्जा के बारे में कुछ जानता है।

पुरातत्व, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों से पता चलता है कि हिंदू मंदिरों को नष्ट करके कई मस्जिदें बनाई गईं। कई स्थलों पर चल रही जांच इस तथ्य का समर्थन कर रही है और हिंदुओं की पूजा स्थल को वैध रूप से वापस करने की मांग अनुचित नहीं है। हालाँकि, इसे एक निरपेक्ष मुद्दा बनाना, गरमागरम बहस को भड़काना और पूरे देश से सिर्फ एक विषय पर ध्यान केंद्रित करने की अपेक्षा करना हिंदुओं या विकासशील राष्ट्र के लिए उचित मानसिकता नहीं है। हमें इस बात की गहन जांच की जरूरत है कि सरसंघचालक मोहन भागवत ने विभिन्न स्थानों पर मस्जिदों के नीचे मंदिर पाए जाने के बारे में मराठी में क्या कहा।

उनके कथन- हमें मस्जिदों के नीचे मंदिर के मुद्दे उठाते रहना नहीं चाहिए और किसी को भी हिंदू नेता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए- का मेरा विश्लेषण।

1. हमारे देश और दुनिया भर में संघर्षों ने हर देश, धर्म और समुदाय में दुख और तनाव पैदा किया है। दुनिया ने विश्वव्यापी शांति के लिए एक अच्छा जवाब खोजने में अपना रास्ता खो दिया है। सनातन धर्म ने पहले ही सार्वभौमिक भाईचारे और शांति का मार्ग प्रदर्शित किया है और हाल के दिनों में, दुनिया एक बार फिर शांति और सद्भाव बहाल करने में सनातन धर्म की शक्ति को देख और मान रही है। दुनिया भर में कई लोगों ने सनातन धर्म का पालन करना शुरू कर दिया है। कई और सही समय का इंतजार कर रहे हैं। भारत या दुनिया भर में सनातन धर्म को लेकर जो भी विवाद उठता है, विभिन्न धर्मों के बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनेता और सनातन अनुयायी अपने दृष्टिकोण के लिए दो सनातनी नेताओं की ओर देख रहे हैं: पीएम नरेन्द्र मोदी और आरएसएस सरसंघचालक मोहन भागवत। दोनों की बड़ी, वैश्विक जिम्मेदारी है कि वे सौहार्दपूर्ण वातावरण को बहाल करें और यह सुनिश्चित करें कि सदियों से क्रूरतापूर्वक हमला किए जाने के बावजूद सनातन धर्म अभी भी सद्भाव और शांति में विश्वास करता है। सभी को धर्मांतरण किए बिना सनातन धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। उनके बयान ने बुद्धिजीवियों के बीच एक अनुकूल लहर पैदा की, जो मानते हैं कि सनातन धर्म के पास उचित उपाय हैं।

2. उन्होंने कभी नहीं कहा कि आरएसएस और उसके सहयोगी यूपी सरकार, किसी अन्य सरकार या विष्णु शंकर जैन जैसे लोगों को हिंदुओं के लिए कानूनी न्याय की लड़ाई छोड़ने के लिए कहेंगे। संवैधानिक कानूनों के अनुसार लड़ाई जारी रहेगी और 1991 के पूजा स्थल अधिनियम और वक्फ बोर्ड अधिनियमों के लिए भी न्यायिक लड़ाई की आवश्यकता है, जिन पर गरीब और मध्यम वर्ग के हिंदुओं और मंदिर ट्रस्ट के स्वामित्व वाली भूमि और मंदिरों के भूमि अतिक्रमण जैसे बड़े मुद्दों को संबोधित करने के लिए ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हिंदुओं को समृद्ध होने के लिए भारत के भीतर और बाहर कई हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करते हुए कई मोर्चों पर कानूनी लड़ाई लड़नी होगी।

3. सरसंघचालक मोहन भागवत और आरएसएस की आलोचना करने वाले हिंदुओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज, भगवान श्रीकृष्ण, प्रभु श्रीराम और चाणक्य का गहन अध्ययन नहीं किया है। अगर हम सोशल मीडिया पर हिंदुओं की भावनाओं पर विश्वास करें तो वे हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज पर भी सवाल उठाएंगे कि उन्होंने मुस्लिम आक्रमणकारियों को कुछ किले दे दिए थे। क्या यह तथ्य कि भगवान श्रीकृष्ण पांडवों के लिए केवल पाँच गाँवों के साथ विवाद को हल करना चाहते थे, इसका मतलब यह है कि वे कायर थे? हमें हर चीज को व्यापक दृष्टिकोण से समझने की जरूरत है, जिसमें उस अवधि के सभी कारकों के प्रकाश में नीति का पालन करना भी शामिल है।

आजकल

विमान हादसों पर सवाल

वर्ष के अंत में दो भीषण विमान दुर्घटनाओं ने हवाई यात्रा की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। कजाकिस्तान में अजरबैजान के विमान और दक्षिण कोरिया में दुर्घटनाग्रस्त विमान ने क्रमश: 38 और 179 लोगों की जान ले ली। हादसों के कारण और बचाव की समीक्षा में जांच जारी है।

साल के आखिरी दिनों में हुई दो भीषण विमान दुर्घटनाओं के कारण जहां दुनिया भर में शोक की लहर है, वहीं इस वजह से हवाई यात्रा की सुरक्षा से जुड़े सवाल भी केंद्र में आ गए हैं। कजाकिस्तान में बुधवार को लैंडिंग करते हुए अजरबैजान के विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 38 लोगों की मौत हुई तो रविवार को दक्षिण कोरिया में हुए हादसे में 179 लोगों के मारे जाने की खबर है। साउथ कोरिया के मुआन में हुए हादसे में जिस तरह से लैंडिंग का प्रयास करते हुए विमान कुछ सेकंड के अंदर ही लपटों से घिरा नजर आया, वह किसी का भी दिल दहला सकता है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लैंडिंग से कुछ ही पहले विमान के पिछले हिस्से से एक पक्षी टकराया था। कहा जा रहा है कि शायद इसी वजह से लैंडिंग गियर में खराबी आ गई। लेकिन कई जानकार इससे सहमत नहीं हैं। संभव है कि हादसे की जांच से कुछ और तथ्य सामने आने के बाद इस पहलू पर और रोशनी पड़े। इस बीच अजरबैजान विमान हादसे को लेकर हो रहे अलग-अलग दावों के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पूतिन की माफी ने सस्पेंस को पूरी तरह खत्म किए बगैर संदेहों को और गहरा कर दिया है। पूतिन ने अपने माफीनामे में यह तो कहा कि जब वह विमान कजाकिस्तान में लैंड कर रहा था तब यूक्रेनी ड्रोन हमलों के मद्देनजर रूसी डिफेंस सिस्टम एक्टिव था, पर यह स्वीकार नहीं किया कि वह विमान इसी सिस्टम का टारगेट बना।

विमान किसी तकनीकी गड़बड़ी का शिकार हुआ या गलती से चली किसी मिसाइल का, सच तो यही है कि इसमें सवार यात्रियों को जान गंवानी पड़ी। एविएशन इंडस्ट्री की ज्यादा चिंता स्वाभाविक ही साउथ कोरियाई विमान हादसे को लेकर है क्योंकि उसे यात्रियों की बढ़ती आशंकाओं का सामना करना है। हालांकि हवाई दुर्घटनाओं के मामले में साउथ कोरिया का रेकॉर्ड अच्छा माना जाता रहा है। यह पिछले एक दशक में हुई साउथ कोरियन एयरलाइन की पहली बड़ी दुर्घटना है।

दुनिया की सोच भी बदल दी एआई ने

डॉ. शशांक द्विवेदी

पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में साल 2024 में कई बड़े बदलाव हुए। एआई सहित कई-कई टेक इनोवेशन सामने आये हैं, जिन्होंने तकनीकी दुनिया को बदलने और लोगों को हैरान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों ने जनरेटिव एआई को अपनाने से लेकर फोल्डेबल स्मार्टफोन की बढ़ती पॉपुलेरिटी तक, एक्सेसिबिलिटी और इंटीग्रेशन को बढ़ाने पर फोकस किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए साल 2024 एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी साल साबित हुआ। इस साल एआई ने तकनीकी विकास में ऐसी छलांग लगाई, जिसने न केवल डिजिटल दुनिया बल्कि आम लोगों की जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल दिया। एआई अब हर सेक्टर में काबिज हो रही है।

5जी की प्रौद्योगिकी ने तेज इंटरनेट स्पीड और कनेक्टिविटी के मामले में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। इसके चलते स्मार्टफोन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 2024 में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी (वीआर/एआर) ने गेमिंग, एंटरटेनमेंट, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में नयी ऊंचाइयों को छुआ है। नये और उन्नत वीआर/एआर हेडसेट्स और एप्लिकेशन का विकास हुआ है। 2024 में मिक्स्ड रियलिटी हेडसेट कंज्यूमर टेक्नोलॉजी में नए सेगमेंट के रूप में सामने आए हैं, जो फिजिकल और डिजिटल इनवायरन्मेंट को सीमलेस ब्लेंड करते हैं। एपल और मेटा जैसे ब्रांड ने ऐसे डिवाइस पेश किए हैं जो वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) को इंटीग्रेट करते हैं ताकि डीप इमर्सिव एक्सपीरियंस ऑफर किए जा सकें।

बीते साल क्वांटम कम्प्यूटर के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आईबीएम और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने अपने क्वांटम कंप्यूटरों के नये वर्शन पेश किये हैं, जिनका उद्देश्य समस्याओं को हल करने की गति को मौजूदा सुपरकंप्यूटर से कई गुना अधिक बढ़ाना है। एआई ने शिक्षा के क्षेत्र में भी नई क्रांति लाने का काम किया। भारत की पहली एआई टीचर के रूप में आइरिस जानी जाती हैं। इस साल मार्च में इन्हें तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी स्कूल द्वारा विकसित किया गया।

वर्ष 2024 में बायोइलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ टेक्नोलॉजी ने स्वास्थ्य देखभाल को एक नयी दिशा दी है। स्मार्ट वियरेबल्स, स्वास्थ्य से संबंधित एप्स और एआई-बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल्स ने मेडिकल क्षेत्र में सुधार किया है। वहीं, सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन टेक की बात करें, तो पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी इस साल इनोवेशन हुआ है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा संरक्षण के नये तरीके सामने आये हैं। ट्रांसपेरेंट टीवी इस साल काफी चर्चा में रहा। ये 77-इंच का एक ट्रांसपेरेंट टीवी है, ये बंद होने पर शीशे की तरह दिखता है। टीवी ऑन होता है तो एक अलग ही तरह विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए ज़ीरो कनेक्ट बॉक्स का यूज किया गया है। वर्ष 2024 में हुआवई ने फोल्डेबल या फ्लिप फोन नहीं बल्कि ट्रिपल फोल्ड फोन लॉन्च किया है। ये दुनिया का पहला ट्रिपल-फोल्ड स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन खुलने पर 10.2 इंच की बड़ी स्क्रीन ऑफर करता है। ये टैबलेट की तरह भी यूज किया जा सकता है। इसमें 1टीबी स्टोरेज है। फोटो-वीडियोग्राफी के लिए चार कैमरा हैं। स्मार्टफोन से कई फोल्डिंग मोड्स में काम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे गैजेट के काम करने के तरीके का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। ये क्रिएटिव और प्रेक्टिकल फीचर्स को एड करती है, जो इन डिवाइसेज के इस्तेमाल के तरीके को बेहतर बनाती है।